Seventeenth Loksabha

>

Title: Presentation of 17th, 18th, 19th, 20th, 21st and 22nd Reports of the Standing Committee on Defence on Demands for Grants.

श्री जुएल ओराम (सुंदरगढ़): महोदय, मैं रक्षा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) 'रक्षा सेवाएं, खरीद नीति, रक्षा आयोजना और विवाहित आवासीय परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय के बारे में वर्ष 2019-20 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (मांग सं. 20)' विषय के बारे में तीसरे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 17वां प्रतिवेदन।

(2) 'रक्षा सेवाएं, खरीद नीति, रक्षा आयोजना और विवाहित आवासीय परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय के बारे में वर्ष 2020-21 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (मांग सं. 20)' विषय के बारे में सातवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 18वां प्रतिवेदन।

(3) 'सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तटरक्षक, रक्षा सम्पदा संगठन, सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों, कैंटीन भंडार विभाग, भूतपूर्व सैनिक कल्याण और रक्षा पेंशन के बारे में वर्ष 2021-22 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की

मांगें (मांग सं. 18 और 21)' के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 19वां प्रतिवेदन।

(4) 'थल सेना, वायु सेना, नौ सेना, संयुक्त स्टाफ, सैन्य अभियांत्रिकी सेवाओं, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना और सैनिक स्कूलों के बारे में वर्ष 2021-22 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (मांग सं. 19 और 20)' के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 20वां प्रतिवेदन।

(5) 'रक्षा सेवाएं, खरीद नीति, रक्षा आयोजना और विवाहित आवासीय परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय के बारे में वर्ष 2021-22 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (मांग सं. 20)' के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 21वां प्रतिवेदन।

(6) 'आयुध निर्माणियां, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय और राष्ट्रीय कैडेट कोर के बारे में वर्ष 2021-22 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (मांग सं. 19 और 20)' के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 22वां प्रतिवेदन।